" एक मानव-केन्द्रित भावी समाज की दिशा में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग" विषय पर भाषण, जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों का शिखर-सम्मेलन, जापान, 3 से 5 नवंबर 2019.

———

जापान की डाइट के हाउस ऑफ काउंसिलर्स की अध्यक्ष महामहिम अकीको सैंटो, आई.पी.यू अध्यक्ष महामहिम गैब्रिएला क्यूवास बैरोन, पीठासीन अधिकारीगण, माननीय सांसदगण, देवियों और सज्जनों :

- जी-20 देशों की संसदों के अध्यक्षों के शिखर-सम्मेलन में मानवता के भविष्य के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय 'एक मानव-केन्द्रित भावी समाज की दिशा में नई प्रौद्योगिकी का उपयोग' पर चर्चा करने के लिए अपने साथी गण्यमान्य सदस्यों के बीच आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है।

- इस विषय पर अपने विचार साझा करने से पहले, मैं जापान की संसद को हमें आमंत्रित करने के लिए तथा टोक्यो जैसे अति सुंदर शहर मे भव्य आतिथ्य प्रदान करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूँ। मैं आई.पी.यू की अध्यक्ष गैब्रिएला क्यूवास बैरोन का भी कृतज्ञ हूँ जिन्होंने इस शिखर सम्मेलन को 2018 में अर्जेंटीना में मूर्त रूप देकर साकार किया।

- आज प्रौद्योगिकी और नई पहलों से समाज और अर्थव्यवस्था में बड़े पैमाने पर बदलाव आ रहे हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स (आईओटी), आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस (एआई) और रोबोटिक्स, ब्लाक चेन, मशीन लर्निंग जैसी नयी टेक्नोलॉजी से हो रहे नए बदलाव विकास के लिए सहायक बन रहे हैं और इससे विकासशील देशों की बढ़ती आकांक्षाओं को पूरा करने का अवसर मिल रहा है।

- प्रौद्योगिकी उपयोग के बारे में भारत का दृष्टिकोण नागरिकों को सशक्त बनाना रहा है। हमारी कार्यनीति में इस बात पर जोर दिया जाता है कि भारत विकास एजेंडा के अनुसार सामाजिक और समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तनकारी प्रौद्योगिकियों का उपयोग कैसे कर सकता है।

- भारत में हम स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और इसे किफायती बनाने; किसानों की आय बढ़ाने, खेतों में उत्पादकता बढ़ाने; शिक्षा तक पहुंच और इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने; सुरक्षित आवागमन सुविधा प्रदान करने जैसे कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रहे हैं।

- भारत के लिए डिजिटलीकरण पारदर्शी समावेशी, सतत और लागत प्रभावी ढंग से 1320 मिलियन लोगों की आशाओं को पूरा करने का अभूतपूर्व अवसर प्रदान कर रहा है।

- डिजिटल मंच पर पहले से ही 2300 से अधिक सेवाएं उपलब्ध हैं।
- अपने स्वतंत्र 'एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस' (एपीआई) के साथ 'आधार' भारत में आ रहे डिजिटल बदलाव की नींव है। आधार के माध्यम से भारत सरकार ने अब तक देश के 1240 मिलियन नागरिकों को डिजिटल पहचान प्रदान की है।
- यूपीआई आधारित भारत इंटरफेस फॉर मनी (भीम) के माध्यम से डिजिटल भुगतान तेजी से बढ़ रहा है।
- वित्तीय समावेशन की योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत 370 मिलियन से अधिक नये लाभार्थियों के बैंक खाते खोले गये हैं। सामाजिक सुरक्षा लाभ सीधे इन बैंक खातों में प्राप्त हो रहे हैं जिससे दक्षता, पारदर्शिता और निगरानी बढ़ रही है।
- भारत में 3 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेन्टर (सीएससी) की स्थापना गांवों में की गई है, जोकि लगभग 300 डिजिटल सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। इन सेवाओं में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रमाणपत्र संबंधी सेवाएं शामिल हैं।
- भारत में डिजिटल बदलाव ने स्त्री-पुरूष असमानता को भी सफलतापूर्वक कम किया है। भारत में आईटी सेवा उद्योग में लगभग 4.14 मिलियन लोग कार्य कर कर रहे हैं जिनमें से 30 प्रतिशत महिलाएं हैं।
- मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि हमारी संसद के कामकाज में भी बहुत बदलाव आ रहा है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से न केवल कामकाज अधिक पारदर्शी और कुशलतापूर्वक हो रहा है बल्कि कार्य का निर्वहन अधिक प्रभावी ढंग से हो रहा है।
- हाल के वर्षों में की गई पहलें - सदस्य पोर्टल; सदस्यों की ऑनलाइन संदर्भ सेवा; संसद डिजिटल लाइब्रेरी; संसद का सफलतापूर्वक डिजिटिकरण कर रही है।
- मैं मानता हूं कि डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग में भारत का अनुभव और इसे प्राप्त सफलता एक अनुकरणीय मॉडल है। प्रौद्योगिकि क्रांति के लाभ सभी देशों और विश्व के सभी लोगों को उपलब्ध कराना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

धन्यवाद।